

**न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 108/2016  
अपीलार्थी:

G.C.M.S. No. 2016/00457

दर्ज दिनांक : 01.12.2016

1. प्रेमदास पुत्र भगवानदास उम्र 58 वर्ष, जाति वैष्णव कवीर पंथी निवासी ग्राम चाटेलाव तहसील रोहट जिला पाली।
2. राजेश पुत्र मोहनलाल उम्र 45 वर्ष, जाति माली निवासी ग्राम मालियों की बस्ती श्रमिकपुरा, मसुरिया, जोधपुर तहसील जोधपुर।

प्रत्यर्थिगण:

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, रोहट व जिला पाली।
2. राजाराम पुत्र उदाराम, उम्र 55 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी चाटेलाव, तहसील रोहट जिला पाली।
3. जयलाल पुत्र गंगाशंकर उम्र 60 वर्ष, जाति श्रीमाली ब्राह्मण निवासी चाटेलाव तहसील रोहट जिला पाली।  
(2) ब्रह्म विहार, बांगड़ कॉलेज के पीछे, पाली।
4. जुंगरराम पुत्र वचना, उम्र 50 वर्ष, जाति देवासी निवासी चाटेलाव तहसील रोहट जिला पाली।
5. मंदिर श्री रघुनाथजी महाराज ग्राम चाटेलाव, तहसील रोहट व जिला पाली।



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर रोहट राजस्व मूल वाद संख्या 37/2013 एवं राजस्व विविध संख्या 58/2013 बअनवान डोली मंदिर श्री रघुनाथजी महाराज बनाम प्रेमदास वगैरह पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

**पैरोकार-**

1. श्री पी.एम. जोशी, श्री सी.पी. सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांत।
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पॉडेंट संख्या 1
3. श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक रेस्पॉडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक: 24.11.2025

अपीलान्त की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रोहट राजस्व मूल वाद संख्या 37/2013 एवं राजस्व विविध संख्या 58/2013 बअनवान डोली मंदिर श्री रघुनाथजी महाराज बनाम प्रेमदास वगैरह पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 92ए, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

के तहत एक वाद ग्राम चाटेलाव की खसरा संख्या 12, 159, 160, 161, 162, 163, 261,

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

291, 302, 303 की भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। वादी की ओर से डोली बनाम मंदिर श्री रघुनाथजी महाराज का शीर्षक अंकित करते हुए संरक्षक राजाराम, पुजारी जयलाल व प्रबंधक डुंगरराम विपक्षीगण को बताते हुए वाद प्रस्तुत किया, साथ ही धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने, प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करने, भूमि अन्तरण सम्बन्धी किसी तरह का दस्तावेज निष्पादित नहीं करने, यथास्थिति बनाये रखने के अनुतोषों के साथ प्रस्तुत किया, वहीं मूल वाद में घोषणा कर उक्त वर्णित भूमि मंदिर श्री रघुनाथजी महाराज के नाम दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथा आदेश पारित करने में अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, न ही कोई जानकारी दी गई है। अन्यथा कोई स्थिति माने जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय की पीठ ग्राम रोहट के अलावा अन्यथा पत्रावली प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु समुचित सूचना-पत्र प्रेषित किया जाना था, जिसके अभाव में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से रद्द किये जाने योग्य है। इसके साथ ही उपखण्ड अधिकारी, रोहट की पीठ ग्राम रोहट में निर्धारित है, परन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री ग्राम बिटू में राजस्व लोक अदालत का कैम्प बताकर वहां प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पीठ का स्थान नोटिफिकेशन के अलावा कहीं परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रथमदृष्टया ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथा आदेश अनुचित रूप से, बिना न्यायालय की पीठ में सुनवाई के पारित किया गया है, यहां तक कि न्यायालय की पीठ का स्थान परिवर्तित बताकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पीठ ग्राम रोहट के अलावा न तो पत्रावली प्रस्तुत हो सकती थीं, न ही निर्णय पारित किया जा सकता था। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथा आदेश में पक्षकारान उपस्थित होना अंकित किया गया है। पक्षकारान व वकील वादी ने हाजा प्रकरण का निस्तारण राजस्व कैम्प में लोक अदालत की भावना से करने हेतु निवेदन करने का भी अंकित किया है, परन्तु अपीलार्थीगण की न तो उपस्थिति है, न ही कोई जानकारी है, न ही सुनवाई है, न ही निवेदन है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के लिए तनकियात निर्मित कर तनकियात के आधार पर साक्ष्य का अवसर प्रदान कर अपीलार्थीगण को समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक था। अपीलार्थीगण की कोई उपस्थिति तनकियात निर्मित होने तक भी नहीं थीं। अपीलार्थीगण की उपस्थिति मात्र विपक्षी वादी के गवाहान



की जिरह के समय ही उपस्थिति हो सकती थी, उसी समय अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती थी। प्रकरण में अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने की न तो स्टेज थी एवं न ही ऐसा आदेश पारित ही किया जा सकता था। वहीं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय कथित सर्कूलरों के आधार पर पारित किया है। सर्कूलर किसी भी रूप से विधि का स्थान नहीं लेते हैं। प्रकरण में वादी पक्ष की कोई साक्ष्य ही नहीं थी, जिससे वाद खारिज योग्य था। इसके विपरीत डिक्री कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध कृत्य किया है। प्रकरण में अपीलार्थी को दिनांक 16.11.16 को कैम्प में राजस्व विविध पत्रावली को निस्तारित करने की जानकारी दी गई। इससे पूर्व हमेशा ही पेशी कैम्प के पश्चात् फाईलें इकट्ठी होने का बताकर नहीं बताई गई थी, जिस पर उसी दिन आवेदन पेश कर प्रमाणित प्रति प्राप्त की। अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर अधिवक्ता ने राजस्व मूल की तारीख पेशी ज्ञात करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर पहले-पहल कोई जानकारी नहीं दी गई, फिर दिनांक 28.11.16 को राजस्व मूल वाद भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा कैम्प में डिक्री किये जाने एवं फैसला करने की जानकारी हुई, जिस पर उसी दिन आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की गई। अधिवक्ता के निर्देश पर माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्थिति प्राप्त करने हेतु पुनः सम्पूर्ण पत्रावली के लिए आवेदन दिनांक 29.11.16 को पेश किया गया, जिस पर उसी दिन नकलें प्रदान की गई, परन्तु पूरी पत्रावली में माननीय न्यायालय का आदेश कहीं अंकित ही नहीं किया गया। राजस्व कैम्प में बाले-बाले, बिना कोई जानकारी दिये, क्षेत्राधिकारविहीन रूप से एवं गलत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एवं राजस्व विविध में आदेश पारित किये गये। चूंकि राजस्व विविध का आदेश भी उसी दिन पारित किया गया है, जो आदेश राजस्व मूल आदेश में समेकित होकर राजस्व मूल भी उसी दिन निर्णित होने से पृथक से अस्तित्व नहीं रहने से इस अपील डिक्री के साथ ही राजस्व विविध के आदेश के विरुद्ध भी अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पोंडेंट संख्या 5 द्वारा अपीलांत के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रथाई निषेधाज्ञा व बेदखली बाबत वादपत्र दिनांक 07.05.2013 को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2016 द्वारा राजस्व कैम्प में खारिज कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांतद्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांत द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि अपीलांत को अपीलाधीन निर्णय की दिनांक 16.11.2016 से पूर्व जानकारी नहीं थी। अपीलांत को उक्त पत्रावली की तारीख पेशी की कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी व न ही कैम्प की कोई सूचना दी गई। दिनांक 16.11.2016 को सूचना प्राप्त होने पर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांत अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में मजम-ए-आम में पारित किया गया है। अतः अपीलांत का यह कथन कि उसे उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी, पूर्णतया मनगढ़ंत कथन है। अपीलांत द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय कारण व आधार प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हों कि उसे दिनांक 16.11.2016 से पूर्व अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं रही हों तथा उसे वस्तुतः दिनांक 16.11.2016 को ही अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई हों। परिसीमा अधिनियम में विहित परिसीमा अवधि के संबंध में विलंब के लिए संबंधित पक्षकार को दिन-प्रतिदिन के विलंब का कारण प्रस्तुत करना आज्ञापक होता है तथा विलंब के ऐसे कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित होना आवश्यक है। अपीलांत प्रार्थी द्वारा दिन-प्रतिदिन के विलंब का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रस्तुत कारण बनावटी होने से युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित नहीं माना जा सकता।
4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-  
condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing  
appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court  
can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason  
given to condone the inordinate delay-Held, Order is not  
sustainable and set aside.

राजस्व अपील प्राधिकारी  
यासी

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 - Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose - No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) - Section 5 & 3 - As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforesaid provision connotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or referred to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.
4. 2024 RBJ 463 (S.C.) - Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158



राजस्व अपील प्राधिकारी  
जापुर

days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 120 दिवस का विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 120 दिवस का विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

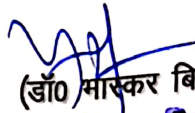
### आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
फली

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर  
सर-ए-इजलास सुनाया गया।



  
(डॉ० मास्कर बिश्नोई)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
पाली